जुमलों और कार्डों से स्वस्थ रखेगी हरियाणा को खट्टर सरकार

आयुष्मान नाटक का मंचन 21 नवम्बर से शुरू

फ़रीदाबाद (म.मो.) जनता को पर्याप्त स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने में पूरी तरह से असफल भाजपा सरकार जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिये जो तरह-तरह के नाटक खेल रही है, उन्हीं में से एक है 'आयुष्मान भारत'। इसी श्रृंखला में स्थानीय सांसद एवं केन्द्रीय मंत्री कृष्णपाल गूजर ने 'चिरायु' शीर्षक से भी एक योजना की घोषणा कर डाली।

सन 2019 के चुनावों से एक वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री मोदी ने 'आयुष्मान भारत' का आविष्कार करके देश की 50 करोड़ जनता को चिकित्सा सेवायें उपलब्ध कराने का डंका पीटा था। शुरू से ही फ्लॉप शो दिखने वाली यह योजना पूरी तरह से फलॉप भी हो गई। चार साल तक मोदीजी मुंह ढक कर सोये रहे। अब 2024 के चुनाव निकट आते देख कर उन्हें फिर से 'आयुष्मान भारत' नजर आने लगा है।

मोदी सरकार ने इस योजना का लाभ उठाने वालों की आय सीमा जहां 1 लाख 20 हजार वार्षिक रखी है वहीं खट्टर सरकार ने इसे 1 लाख 80 हजार तक कर दिया है। ऐसा इसलिये करना पड़ा कि पुरानी शर्त के दायरे में आने वालों की संख्या बहुत ही कम रह गई है। नई आय सीमा की पालना भी सख्ती से नहीं कराई जा रही। मक्सद केवल इतना है कि भाजपा कार्यकर्ता इस फ़र्जी योजना के तहत 'लाभान्वित' होने वालों का एक अच्छा-खासा समूह अपने इर्द-गिर्द बना लें जिन्हें चुनाव के वक्त हांक कर मतदान केन्दों तक लाया जा सके।

जनता के प्रति इस सडयंत्र के तहत 21 नवम्बर को बीके अस्पताल में ज़िला प्रशासन की ओर से 'आयुष्मान कार्ड' वितरण समारोह आयोजित किया गया। इसमें जिले के तमाम उच्च प्रशासनिक तथा चिकित्सा अधिकारी तो शामिल थे ही, स्थानीय विधायक व मंत्री भी अपनी-अपनी कलाकारी दिखाने आ पहुंचे। गोदी मीडिया की सहायता से बहला-फुसलाकर लाई गई जनता को बताया गया कि इस कार्ड के द्वारा उनको मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान की जायेगी। बहकावे के चलते उमड़ी भीड़ में से करीब आधे लोग ऐसे थे जिनके नाम कार्ड पाने वालों की सूची में नहीं थे। वे इधर से उधर तमाम छोटे-बड़े अधिकारियों के चक्कर लगाने के बाद थक-हार कर एक तरफ़ बैठे सरकार को कोस रहे थे।

वैसे, जिनके कार्ड नहीं बने उन्हें कोई बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मिलना उन्हें भी कुछ नहीं है जिनके कार्ड बन गये हैं। हां, शीघ्र ही इसी बीके अस्पताल में दो तरह के मरीज नजर आने लगेंगे, एक कार्ड वाले और दूसरे बिना कार्ड वाले। सरकार के आदेशानुसार डॉक्टरगण जब कार्डधारकों को प्राथमिकता देने लगेंगे तो बिना कार्ड वाले मरीज चुप तो नहीं रहेंगे। हल्ला-हंगामा होगा और एक नया बबेला अस्पताल में खड़ा हो जायेगा।

लोगों को जो एक बड़ी भारी गलतफहमी है कि इस कार्ड के द्वारा उनका इलाज शहर के पंचतारा व्यापारिक अस्पतालों में होने लगेगा, शीघ्र ही दूर हो जायेगी। अधिकांश बीमारियों के लिये उन्हें सरकारी अस्पतालों के ही चक्कर काटने होंगे। लफ्फाजी के अतिरिक्त सरकार अपने

इन अस्पतालों की स्थिति सुधारने के लिये कुछ भी नहीं कर रही है। और तो और मौजूदा रिक्त पड़े पदों को भरने तक का कोई प्रयास नजर नहीं आ रहा है। हां, घोषणायें व शिलान्यास करने में पूरी महारत रखने वाली भाजपा सरकार ने बीते सप्ताह राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू के हाथों सिरसा में एक मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करवा दिया है। इसके अलावा बीते करीब पांच साल से रिवाड़ी के निकट बनने वाले एम्स के वचन को भी पहली दिसम्बर को खट्टर ने फिर से दोहरा दिया है।

ध्यान रहे कि बीते आठ साल में खट्टर सरकार ने कोई भी नया मेडिकल कॉलेज बनाना तो दूर, छांयसा में बना-बनाया कॉलेज चालू करना भी भारी पड़ रहा है। जो चार कॉलेज सरकार चला भी रही है उनमें भी पर्याप्त स्टाफ़ नहीं हैं। भाजपा सरकार की यही तो जादूगरी है न तो अस्पताल बनायेंगे और न ही सटाफ़ भर्ती करेंगे, केवल कार्डों व जुमलों से ही सबका इलाज कर देंगे।

सिरसा में मेडिकल कॉलेज और रिवाड़ी में एम्स ?

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

बीते सप्ताह गीता महोत्सव के सिल-सिले में कुरूक्षेत्र आई राष्ट्रपति मुर्मू के डिजिटल कर कमलों से सिरसा में बनने वाले एक मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास कराया गया है। खट्टर सरकार की अक्ल का नमूना देखिये कि इसके लिये कुल 21 एकड़ ज़मीन ली गई है। एक ओर तो सरकार कहती है कि अस्पतालों की बिल्डिंग सात मंजिल से ऊपर नहीं होनी चाहिये और दूसरी ओर मात्र 21 एकड़ जमीन पर मेडिकल कॉलेज बनाने जा रहे हैं। संदर्भवश रोहतक का मेडिकल कॉलेज 250 एकड़ में है। सबसे कम जगह, 30 एकड़ में फरीदाबाद का ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज है। इसमें आज जगह की सख्त कमी महसूस की जा रही है। इससे निपटने के लिये कई विकल्पों पर विचार हो रहा है।

रिवाड़ी के निकट माजरा गांव में बनने वाला मेडिकल कॉलेज, जिसे एम्स का नाम दिया गया है। इसकी घोषणा फ़रवरी 2019 में की गई थी। उस वक्त इसके लिये मनोठी गांव में ज़मीन अधिगृहित कर ली गई थी। बाद में वन विभाग ने इस पर आपत्ति लगा दी तो नई जगह माजरा गांव में खोजी गई। यहां 60 एकड़ ज़मीन तो पंचायत से ले ली गई है, 104 एकड़ ज़मीन किसानों से खरीद ली गई है तथा 100 एकड़ से अधिक ज़मीन अभी खरीदी जानी बाकी है। कछुआ चाल से होती इस प्रगति को देखकर सुधी पाठक बखूबी समझ सकते हैं कि यह एम्स कितने दसकों में पूरा होकर चालू हो सकेगा।

यदि सरकार को जनता व अक्ल से दुश्मनी न होती तो झज्जर जिले के बाडसा गांव में पहले से ही 250 एकड़ में बन रहे अधूरे एम्स को ही पूरा कर लेते और रिवाड़ी के बजाय हिसार अथवा जींद की ओर नये एम्स का निर्माण करते। झज्जर वाले एम्स को बीच में छोड़कर दिल्ली के ही एम्स तथा सफदरजंग अस्पताल में ही घुसमुस करके विस्तार कार्य कर रहे हैं। विदित है कि दिल्ली एम्स के विस्तार के लिये ही बाडसा को चुना गया था। अब चुकी उस पर हुड्डा सरकार की मुहर लग चुकी थी इसलिये उसको भला कैसे पूरा होने दे सकती है मौजूदा संघी सरकार ?

खट्टर के झांसे में आने वाले नहीं मेडिकल छात्र

रोहतक करनाल (म.मो.) खट्टर की जनविरोधी, विशेषकर मेडिकल शिक्षा विरोधी नीति के विरोध में छात्रों का आन्दोलन एक माह की सीमा पार कर चुका है। छात्रों द्वारा दी गई चेतावनी के अनुसार ओपीडी तथा वार्डों की सेवायें भी करीब दो सप्ताह से ठप्प पड़ी हैं। इसके बावजूद खट्टर अपनी मूर्खतापूर्ण तथाकथित बांड पॉलिसी पर अड़े हुए हैं। **'मज़दूर मोर्चा'** कई बार लिख चुका है कि यहां बांड शब्द का गलत इस्तेमाल हो रहा है। इसे बांड न बता कर सीधे-सीधे फीस बढोत्तरी कहा जाना चाहिये।

डॉक्टरी पढाई से सम्बन्धित छात्रों को अपने से अधिक मूर्ख समझने वाले खट्टर ने वीरवार को, छात्रों से हुई वार्ता में नया प्रस्ताव रखते हुए कहा कि बांड राशि को घटा कर 30 लाख तथा सात साल की सरकारी नौकरी की जगह पांच साल की शर्त रखी है। इसके साथ-साथ एक साल के भीतर सरकार उन्हें नौकरी में भर्ती कर लेगी। अजीब मजाक है। पासआउट होकर डॉक्टर साहब एक साल तक खाली बैठ कर खट्टर साहब द्वारा भर्ती किये जाने का इंतजार करेंगे और उसके बाद पांच साल की नौकरी करने पर उनके बैंक लोन का भुगतान सरकार करेगी।

झूठ के पहियों पर चलने वाली इस सरकार का विश्वास भला कौन कर सकता है ? एक साल की कह कर ये दो-तीन साल भी भर्ती न करें तो कोई इनका क्या बिगाड़ लेगा ? छात्रों का स्पष्ट कहना है कि वे इस झांसे में कतई फसने वाले नहीं हैं। सीधी स्पष्ट दो टूक बात यह है कि बांड राशि घटाने की बजाय सरकार नौकरी की गारंटी दें और जो कोई नौकरी करने से इनकार करे, उससे बांड राशि वसूली जाय। पूरी दुनियां में बांड का यही मतलब होता है। इसी देश में ईएसआई कार्पोरेशन एक साल की सेवा शर्त न मानने वालों से पांच लाख (जो पहले 10 लाख थे) की वसूली करती है।

खट्टर व मोदी जैसे संघ प्रशिक्षित प्रचारकों को जनआन्दोलनों की भाषा जल्दी से समझ नहीं आती। कई बार तो साल भर से भी अधिक समय लग जाता है। इस बीच देश का कितना भारी नुक्सान हो जाता है, वह इनकी समझदानी में नहीं घुस पाता। राज्य के चारों मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा सेवायें पूरी तरह से ठप्प होने के चलते आम जनता पर क्या बीत रही है, उसे समझने एवं महसूस करने की योग्यता एवं रूचि खट्टर में कहीं से भी नजर नहीं आती।

बसई के ग्रामीणों ने गांव से भगाया दुष्यंत चौटाला को

गुड़गांव (म.मो.) भाजपा की कृपा से बने उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला अपनी 'जेजेपी' का जनाधार बढाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रयास में वे 30 नवम्बर को, शहर से सटे गांव बसई पहुंचे थे। इस गांव में वे अपनी पार्टी का कार्यालय स्थापित करने आये थे। जिनके भरोसे पर वे इस गांव में अपना आधार बनाना चाहते थे, वे पूरी तरह से नंगड़ थे। यूं भी चौटालों के पास कोई ढंग के आदमी तो कम ही जाया करते हैं, अधिकांश नंगड़ एवं सत्ता की दलाली करने वाले ही जुटते हैं। ऐसे ही लोगों के भरोसे दुष्यंत बसई गांव जा पहुंचे।

गांव के नंगड़ों ने चौटाला को आमंत्रित तो कर लिया लेकिन ग्रामीणों की भीड़ जुटाने के लिये उनके पल्ले धांस भी न थी। ऐसे में इन नंगड़ों ने गांव की बेटी सिमरन कटारिया जो कि जुडो में एशियन व ओलम्पिक मेडलिस्ट है, को चौटाला द्वारा सम्मानित करने के नाम पर भोपाल से बुलवा लिया। पल्ले से 13 हजार रुपये खर्च करके तथा काम छोड़कर सिमरन गांव में आ तो गई, परन्तु सम्मानित करना तो दुर चौटाला ने बिटिया को स्टेज पर भी नहीं आने दिया। इस बावत नंगड़ों द्वारा बार-बार अनुरोध किये जाने के

बावजूद चौटाला स्टेज से उतर कर अपने तथाकथित नवनिर्मित कार्यालय में जा बैठे और चाय पीने लग गये। ज्यादा अनुरोध किये जाने पर चौटाला ने कहा कि उसे दफ्तर के अंदर ही ले आओ, यहीं सम्मानित कर देंगे।

यह सुनकर सारा गांव आग बगुला हो गया। सिमरन कटारिया ने भी चौटाला को खुब खरी-खोटी सुनाते हुए कहा कि वह तो अन्तराष्ट्रीय स्तर पर पहले से ही काफ़ी सम्मानित हो चुकी है, उसे चौटालों जैसों से सम्मानित होने की कतई कोई जरूरत नहीं है। दरअसल गांव की आबादी का 60 प्रतिशत में तो सिमरन का ही परिवार बसा है। सिमरन को सम्मानित करने का तो बहाना मात्र ही था, इस बहाने सारा गांव चौटाला की जनसभा में जोड़ कर नंगड़ अपनी पीठ थपथपाना चाहते थे। अंत में इस धोखाधड़ी का परिणाम यह निकला कि सारे गांव ने चौटाला के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की, काले झंडे दिखाये और गांव से भागने को मजबूर कर दिया। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि एक कमरे में चौटाला का दफ्तर खोल कर पूरी अवैध निर्मित बिल्डिंग को बचाने का उद्देश्य था।

दुष्यंत के दादा एवं तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला भी इन्हीं ग्रामीणों से उस वक्त उखड़ गये थे जब ग्रामीणों की ओर से उन्हें माला पहनाने के लिये एक विकलांग को स्टेज पर चढ़ा दिया गया था।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 708 सैक्टर-14 फरीदाबाद से प्रकाशित किया।